भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1753**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

वृक्षारोपण क्षेत्र

1753. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वृक्षारोपण क्षेत्र बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है क्योंकि इस क्षेत्र को विशेषकर दक्षिण भारत में लाभकर मूल्य नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्य किए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि पण्य बोर्डों में बजटीय आवंटन में कटौती के कारण इन बोर्डों की स्वीकृत योजनाओं के लिए उत्पादकों की काफी राशि बकाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में वृक्षारोपण क्षेत्र को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क): अन्य क्षेत्रों के साथ- साथ, बागान क्षेत्र पर भी कोविड-19 **महामारी के प्रकोप का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।**

हालांकि, कोविड-19 **के दौरान लॉकडाउन के कारण चाय के उत्पादन में कुछ कमी आई है, इसने बाजार में अधिक आपूर्ति की स्थिति को कम कर दिया जिससे उद्योग को विनिर्मित चाय की औसत कीमत प्राप्ति में वृद्धि में मदद मिल सकती है। वर्तमान वर्ष** 2020-21 **(अप्रैल-अगस्त) के दौरान, चाय की अखिल भारतीय नीलामी कीमतों में विगत वर्ष की तुलना में 67.72 रूपए प्रति कि.ग्रा सुधार (**45.62 % **वृद्धि) हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में विगत वर्ष की तुलना में** 25.42 **रूपए का सुधार** (25.56% **वृद्धि) हुआ है। चाय उद्योग के समग्र कल्याण के लिए चाय की कीमतों और गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जाती है ।**

कॉफी की कीमतें वैश्विक बाजार कारकों पर निर्भर करती हैं। कॉफी की घरेलू खरीद कीमतें अंतरराष्ट्रीय कॉफी कीमत के उतार चढ़ाव से जुड़ी होती हैं । अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन (आईसीओ) के अनुसार, औसत आईसीओ समग्र संकेतक कीमत 2016 **में 127.31 सेंट / पौंड की**

तुलना में 2019 के दौरान घटकर 100.52 यूएस सेंट / पौंड हो गया । तथापि, विगत दो माह में कॉफी की कीमतों में तेजी देखी जा रही हैं जो अगस्त 2020 में 114.78 सेंट / पाउंड हो गयी। एकीकृत कॉफी विकास परियोजना के माध्यम से कॉफी बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए कॉफी क्षेत्र को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

वर्ष 2020 के प्रारंभिक महीनों के दौरान प्राकृतिक रबर (एनआर) की कीमतें 130 रूपए प्रति कि.ग्रा. (आरएसएस 4 श्रेणी) के ऊपर स्थिर रही, तथा लॉकडाउन की अवधि के दौरान इसमें गिरावट देखी गई । इसके बाद, कीमतों में स्थिरता आई और अगस्त 2020 से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जो सितम्बर 2020 में 133 रूपए प्रति कि.ग्रा. तक पहुँच गयीं। रबर उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने शुष्क रबर आयात पर शुल्क को " 20 प्रतिशत या 30 रूपए प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो " से बढ़ाकर " 25 प्रतिशत या 30 रूपए प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो " को 30.04.2015 से प्रभावी कर दिया तथा अग्रिम लाइसेसिंग स्कीम के तहत आयातित शुष्क रबर के उपयोग की अवधि को 18 माह से घटाकर 6 माह कर दिया गया।

कोविड लॉकडाउन के पश्चात इलायची (छोटी) की औसत कीमत में जून माह में 1502.19 रूपये प्रति कि.ग्रा. से अगस्त, 2020 माह में 1683.13 रूपये प्रति किलोग्राम तक उर्ध्वमुखी रूझान रहें । इलायची के किसानों को सहायता देने के उद्देश्य, मसाला बोर्ड ने इलायची की ई-नीलामी को पुन: आरम्भ किया है तथा विभिन्न प्रमाणपत्रों को आनलाइन जारी करने, विभिन्न रिटर्न की समय सीमा में वृद्धि करने, वर्चुअल क्रेता - विक्रेता बैठकें आयोजित करने आदि के लिए सक्षम बनाया है । मसाला बोर्ड ने इलायची उत्पादकों के मध्य एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) अभ्यासों को लोकप्रिय बनाने और इलायची में कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए जैव नियंत्रण एजेंटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख इलायची ऊपज वाले क्षेत्रों में कई अभियान चलाए हैं।

(ख) से (घ): वर्ष 2019-20 में कमोडिटी बोर्ड को 705.21 करोड़ रूपए का बजटीय आवंटन किया गया । वर्ष 2020 -21 के लिए बोर्ड का बजटीय आवंटन 766.34 करोड़ रूपए का है । इस प्रकार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है । माध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) (2017-18 से 2019 -20) स्कीमों को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है ।

इसके अलावा, सरकार ने एमटीएफ के अंतर्गत इन बोर्डों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के माध्यम से उत्पादकों और उद्योग को नव रोपण, पुन: रोपण, कायाकल्प, गुणवत्ता उन्नयन, मूल्य संवर्धन और बाजार संवर्धन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके बागान क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अलग - अलग कमोडिटी बोर्डो के माध्यम से विभिन्न पहलें की हैं।

****